योजनाओं के कार्यान्वयन की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिए है, यदि हां, तो अगस्त, 1991 तक प्राप्त हुए आवेदन पत्र की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इन आवेदन पत्रों पर अक्तूबर, 1991 के अन्त तक कोई निर्णय नहीं लिया है; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार भविष्य में ऐसे मामलों के तुरन्त निपटान के लिए मार्ग निर्देश बनाने का विचार रखती है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां । सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि जिन कम्पनियों ने 6 से 8 महीने पहले अपने आवेदन प्रस्तुत किए थे उन्हें अभी मंजूरी दी जानी है ।

(ख) संयुक्त उद्यमों, पट्टेदारी और परीक्षण मात्स्यिकी पर मार्च, 1991 में नई नीति की घोषणा के बाद उक्त नीति के अन्तर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अगस्त, 1991 तक 4 आवेदन प्राप्त हुए थे ।

(ग) और (घ) दो आवेदन पत्रों के संबंध में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है । शेष दो आवेदन पत्रों की संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है ।

Allocation of edible oil to Gujarat

2132. SHRI VITHALBHAI M. PATEL:
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:
SHRI CHHOTUBHAI PATEL:
SHRI JITENDRABHAI LABHSHANKER BHATT:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any demand has been placed by State Government of Gujarat to the Central Government for the allocation of import edible oil;

(b) if so, what is the monthly demand and alloction for the State for the year 1991-92; and

(c) whether Government propose to import Palmolein oil during the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) The demand and allocation of edible oil for Gujarat for the year 1991-92, month-wise, are as under:—

(Quantity in MTs)

Month	Demand	Allocation
April, 1991	20,000	Nil
May, 1991	20,000	Nil
June, 1991	20,000	Nil
July, 1991	20,000	Nil
August, 1991	20,000	100
September, 1991	20,000	Nil
October, 1991	20,000	1500
November, 1991	8,000	1500

(c) Yes, Sir.